



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 3 — उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राप्तिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० ९]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी २, १९७९/पौष १२, १९००

No. 9]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 2, 1979/PAUSA 12, 1900

इस भाग में विभिन्न पृष्ठ संख्या की जारी हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate packing is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

मंत्रिमंडल संरचनालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 1978

का. आ. 10(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम घोषणा हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारत सरकार (कार्य आबंटन) (एक साँ इकतीसवां संशोधन) नियम, 1978 है।
- (2) ये नियम तुरन्त प्रकृत होंगे।

2. भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961, की वित्तीय अनुसूची में, “गृह मंत्रालय” शीर्षक के अन्तर्गत, “क्रान्तिक और प्रशासनिक सुधार, विभाग” उपशीर्षक के नीचे पर्याप्त 22 के पश्चात, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“22(क) मूल नियमों अनुप्रकृत नियमों और सिर्वल सेवा नियमों सहित सभी सेवा नियमों का (निम्नलिखित क्रौ छाँड़ कर) प्रशासन :—

- (1) कर्मचारियों के वैतन ढाँचे के पुनरीक्षणों में सम्बन्धित प्रस्ताव ;

- (2) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के वैतनमानों के पुनरीक्षणों के लिए प्रस्ताव ;
- (3) वैतन आयोग की नियुक्ति, सिफारियों का प्रसंस्करण और उनका कार्यान्वयन ;
- (4) महंगाई भत्ता और अन्य प्रतिपूर्क भत्ते और यात्रा भत्ते ;
- (5) पौशन ढाँचा और पौशनभौगियों को सहायता ;
- (6) सेवा भर्ती अथवा महत्वपूर्ण आयर्ती वित्तीय निहिताधीं वाले अनुपंगी हितलाभों के रूप में सरकारी कर्मचारियों को कोई नई सुविधा ;
- (7) प्रमुखतः वित्तीय प्रकृति के सेवा नियमों में संशोधनों से सम्बन्धित मामले ;
- (ख) सेवा शर्तों और महत्वपूर्ण आयर्ती वित्तीय निहिताधीं वाले अनुपंगी हितलाभों के रूप में सरकारी कर्मचारियों को नई सुविधा के लिए प्रस्तावों का उपकरण ;
- (ग) खण्ड (क) की मध्य (7) में उल्लिखित प्रमुखतः वित्तीय प्रकृति के सेवा नियमों सहित सेवा नियमों में संशोधनों से संबंधित मामलों में भारत सरकार के आपचारिक आदेश जारी करना।

(घ) धीर्घविरीध वित्तीय निहिताथा^० बाले किन्हीं भी संवा नियमों
का विस्त मंशालय के परामर्श से शिरीखलन और उदारी-
करण।"

नीलम संजीव रेड्डी, राष्ट्रपति,
[सं. 74/2/78-सी. एफ.]
के. सहगल, संयुक्त सचिव,

CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 1978

S. O. 10(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (One hundred and thirty-first Amendment) Rules, 1978.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Second Schedule to the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, under the heading "MINISTRY OF HOME AFFAIRS (GRIH MANTRALAYA)" under the sub-heading "DEPARTMENT OF PERSONNEL AND ADMINISTRATIVE REFORMS (KARMIK AUR PRA-SHASANIK SUDHAR VIBHAG)", after entry 22, the following entry shall be inserted, namely :—

"22A (a) The administration of all service rules including F. Rs. S. Rs and C. S. Rs except—

- (i) proposals relating to revisions of pay structure of employees;
- (ii) proposals for revisions of pay scales of Central Government employees;
- (iii) appointment of Pay Commission, processing of the recommendations and implementation thereof ;
- (iv) dearness allowance and other compensatory allowances and travelling allowances ;
- (v) pension structure and relief to pensioners ;
- (vi) any new facility to Government employees by way of service conditions or fringe benefits which involve significant financial implications ;
- (vii) matters relating to amendments to service rules having a predominantly financial character.
- (b) initiation of proposals for new facility to Government employees by way of service conditions and fringe benefits involving significant recurring financial implications.
- (c) issue of formal orders of the Government of India in matters relating to amendments to service rules including those having a predominantly financial character referred to in item (vii) of clause (a).
- (d) relaxation and liberalisation of any service rules having a long-term financial implications in consultation with the Ministry of Finance."

N. SANJIVA REDDY, President.

[No. 74/2/1/78-CF]

K. SAIGAL, Joint Secy.